Government to fulfil its statutory obligation and constitute an appropriate Tribunal within a period of one month. The matter is being processed accordingly.

(c) No such proposal has been received at the Centre.

(d) and (e). Do not arise.

Income-tax exemption on donations for Jawahar Rojgar Yojna

1756. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government had received any proposal for granting exemption from income-tax the donations given for Jawahar Rojgar Yojna; and

(b) if so, what decision has been taken by Government thereon?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) Yes, Sir.

(b) Sections 35CCA and 80GGA of the Income-tax Act already provide for complete deduction in respect of donations to the Jawahar Rojgar Yojna, if routed through the National Fund for Rural Development.

मध्य प्रदेश में विकास-कार्यों को कार्यान्वित करने के लिये पश्चिमी जर्मनी के साथ समझौता

1757. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 23 अक्तूबर, 1977 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवा-आयाकट में विकास-कार्यों को कार्यान्वित करने के लिये 4 करोड़ 50 लाख ड्यूश मार्क का ऋण उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार और जर्मन संघीय गणराज्य के बीच समझौता हुआ था; यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1989 तक कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) क्या समझौते में निर्धारित शर्तों के अनुसार तवा-आयाकट में सभी विकास कार्य पूरे हो चुके हैं; और

(ग) मध्य प्रदेश में चम्बल नियंत्रण क्षेत्र के विकास हेतु विश्व बैंक से अब तक कितनी धनराशि प्राप्त हुई है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री): (क) जी हां, कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले क्षेत्र में कमी के कारण ऋण की राशि बाद में घटाकर 193 लाख ड्यूश मार्क की गई थी। इस राशि का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा चुका है।

(ख) इस परियोजना के भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 39015.786 हैक्टेयर भूमि को शामिल किया गया है। जिन क्रियाकलापों को अपनाया गया है वे हैं —जल निकास, सड़कें, गहन कृषि-विस्तार अनुकूल अनुसंधान परीक्षण, सर्वेक्षण, योजना, खेत पर विकास, भूमि की चकबन्दी, फसल मुआवजा, बाड़ाबंदी आदि।

(ग) इस प्रयोजन के लिए 550 लाख अमरीकी डालर की विश्व बैंक सहायता का उपयोग कर लिया गया है।

मैसर्स गोल्डन इन्टरप्राइजेज, दानापुर (बिहार) के बीमा संबंधी दावे

1758. **श्री राम अवधेश सिंह:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गोल्डन इन्टरप्राइजेज दानापुर, बिहार ने स्टेट बैंक, दानापुर के माध्यम से नैशनल इंश्योरेंस कंपनी पटना के साथ अपना बीमा कराया था, जिसमें बाढ़ का खतरा भी शामिल था;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1975 की ऐतिहासिक बाढ़ के कारण गोल्डन इन्टरप्राइजेज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और उक्त कारखाना उसी समय से बंद है तथा बीमा कंपनी द्वारा उसे अब तक कोई भुगतान नहीं किया गया है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) का उत्तर "हां" हो, तो सरकार इस संबंध में कब तक दावों का निपटारा करने तथा कंपनी को भुगतान करने का विचार रखती है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री): (क) मैसर्स गोल्डन इन्टरप्राइजिज, दानापुर (बिहार) ने आग, दंगों तथा हड़ताल के जोखिमों के लिए, न कि बाढ़ के जोखिम के लिए भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से नेशनल इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड, से बीमा पालिसी प्राप्त की थी।

(ख) और (ग). चूंकि इस मामले में "बाढ़

कवच" की व्यवस्था नहीं की गई थी। इसलिए बीमा कम्पनी ने इस दावे को सितम्बर, 1977 में अस्वीकृत कर दिया था।

Vocation of stay order obtained from Bombay High Court by Chairman, Bombay Dyeing

1759. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:
SHRI SURESH PACHOURI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1619 given in the Rajya Sabha on the 9th March, 1989 and state:

(a) whether the stay obtained from the Bombay High Court by the Chairman, Bombay Dyeing against the adjudication proceedings initiated against him by the Directorate of Enforcement has since been vacated; and

(b) if so, what is the present position of the case and by when the proceedings are likely to be completed?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) No, Sir.

(b) The matter being *sub-judice*, it is not possible to say as to when the proceedings are likely to be completed.

Evasion of excise duty by M/s. Dunlop India Limited, M/s. Orson and Nihon Company Limited etc.

1760. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that excise duty amounting to crores of rupees has not been paid by M/s. Dunlop India Limited, M/s. Orson and Nihon Company Limited, M/s. Shaw and Wallace Company Limited and M/s. Videocon Co. Ltd.; and

(b) if so, what are the details thereof during the last five years?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Realisation of penalty imposed on Shri R.N. Goenka for income tax returns

1761. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1312 given in the Rajya Sabha on the 30th April, 1987 and state:

(a) whether Government have since realised the penalty imposed on Shri R.N. Goenka for the income-tax returns for the years 1972-73 and 1973-74;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) if the answer to part (b) above be in the negative, by when the amount is likely to be realised and the steps being taken in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) and (b). The penalty amounts of Rs. 3,61,187 and Rs. 2,83,861 levied for the assessment years 1972-73 and 1973-1974 respectively, have since been realised.

(c) Does not arise.

RBI's opinion about banks' balance sheets

1762. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether RBI has opined that the banks' balance sheets conceal more than they reveal;

(b) whether RBI has refused to give autonomy to commercial banks; if so, what are the reasons therefor; and

(c) what action is proposed to be taken by Government to make the banks reveal in their balance sheets the real state of affairs?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) to (c). All commercial banks including the public sector banks, are required to prepare their Profit &